द आसेंडर

पत्रिका
(इलेक्ट्रॉनिकी बितरण हेतु)

मई–जून 2021

सुर्खियां

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
ओडिशा राज्य केंद्र
यूनिट - IV, सचिवालय मार्ग,
भुवनेश्वर - 751001
दूरभाष: +91 - 674 - 25408438
www.nic.in www.gov.in
ई-मेल: sio-ori@nic.in

"To kill an error is as good a service as, and sometimes even better than, the establishing of a new truth or fact."

– Charles Darwin

ओडिशा के माननीय मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने ई-फाइलिंग और ई-पे पोर्टल लॉन्च किए

ओडिशा के माननीय मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री एस मुरलीधर ने एनआईसी की ई-कोर्ट परियोजना के तहत ई-फाइलिंग और ई-पे पोर्टल लॉन्च किए

ओडिशा की "ई-कोर्ट्स" परियोजना ने राज्य भर में 244 न्यायालय प्रतिष्ठानों में मामलों की ऑनलाइन फाइलिंग के लिए "ई-फाइलिंग" पोर्टल (https://efiling.ecourts.gov.in/or/) और कोर्ट फीस के भुगतान के लिए "ई-पे" पोर्टल https://pay.ecourts.gov.in/epay/) लॉन्च करके एक और मील का पत्थर हासिल किया ।

उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने इन पोर्टलों का शुभारंभ किए। उन्होंने उच्च न्यायालय परिसर में न्यायालय शुल्क के ई-भुगतान के लिए एक सुविधा केंद्र, प्रत्येक जिला न्यायालय परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिन और 78 तालुका न्यायालय परिसरों में ई-सेवा केंद्रों का भी उद्घाटन किए।

उच्च न्यायालय की कंप्यूटर समिति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओडिशा राज्य भर के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत जिला न्यायाधीशों, महाधिवक्ता, न्यायिक अधिकारियों, उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और रजिस्ट्री के अधिकारी, और वकीलों सहित एक सौ पचास से अधिक न्यायालय स्थानों की एक सभा को संबोधित करते हुए, ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश ने इन ई-सेवाओं को शुरू करने के पीछे के उद्देश्यों पर जोर दिए और राज्य में न्यायिक प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों को अपनाने का आह्वान किए।

राष्ट्रीय डेटा केंद्र, भुबनेश्वर को अपनी सेवाओं के लिए आईएसओ प्रमाणन

ओडिशा के लिए यह गर्व की बात है कि एनडीसी भुवनेश्वर को आईएसएमएस और आईटीएसएम मानक (आईएसओ/आईईसी 27001:2013 और आईएसओ 2000-1:2018) के साथ "आईएसओ प्रमाणित संगठन" के रूप में प्रमाणित किया गया है। आईटी सेवा प्रबंधन प्रणाली और सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के संचालन के लिए जो आवश्यकताओं का अनुपालन करती है।

एनडीसी भुवनेश्वर में राष्ट्रीय महत्व की कई परियोजनाओं की मेजबानी की जाती है। एनडीसी भुवनेश्वर में क्लाउड होस्टिंग के लिए नई तकनीक और संचालन प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। टीकाकरण कार्यक्रम की निगरानी और प्रबंधन की शुरुआत COWIN पोर्टल के साथ हुई, जो वर्तमान में cowin.gov.in पोर्टल है, जो राष्ट्रीय डेटा केंद्र, भुवनेश्वर में आपदा केंद्र के रूप में सह-होस्ट है। यह पोर्टल आपके मोबाइल नंबर और आईडी प्रूफ का उपयोग करके स्व-पंजीकरण प्रदान करता है। टीकाकरण के लिए नजदीकी वैक्सीन सेंटर का स्थान चुना जाता है और फिर स्लॉट बुक किया जाता है।

eLottery ब्यबस्था eAbkari परियोजना में सामिल हुआ

राज्य भर में रिटेल OFF और CL दुकानों का निपटान एनआईसी, बंगाल और एनआईसी, ओडिशा के संयुक्त प्रयास से पूरा हुआ और eAbkari परियोजना की अन्तर्गत "ई-लॉटरी" प्रणाली के सफल विकास और कार्यान्वयन के माध्यम से पूरा किया गया।

देश भर में लगभग 1500 CL और OFF दुकानों ने भाग लिया और लगभग 22,000 आवेदन प्राप्त हुए। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से अंजाम दिया गया। इस प्रणाली से एक महीने के भीतर लगभग 250 करोड़ रुपये आय हो पाया हे ।

परियोजना को श्री सुशील कुमार लोहानी, आईएएस, प्रमुख सचिव, श्री आशीष सिंह, आईपीएस, आबकारी आयुक्त, आबकारी विभाग, ओडिशा सरकार के सक्रिय नेतृत्व के साथ विकसित और कार्यान्वित किया गया था।

eAbkari का उपयोग उत्पाद शुल्क डोमेन में ERP पैकेज के रूप में किया जा रहा है और यह देश के 10 से अधिक राज्यों में परिचालित है।

भुवनेश्वर में राष्ट्रीय डेटा केंद्र

डीडीजी और एसआईओ, ओडिशा ने गंजाम, आरडीसी बरहामपुर और गजपति का दौरा किया

श्रीमती कबिता रॉय दास, डीडीजी और एसआईओ, एनआईसी, ओडिशा और श्रीमती। निरुपमा महापात्रा, एसटीडी और एएसआईओ ने हाल ही में छत्रपुर में एनआईसी, गंजम जिला इकाई और आरडीसी कार्यालय, बेरहामपुर में एनआईसी इकाई का दौरा किया है।

एसआईओ और एएसआईओ, गंम के डीआईओ और एडीआईओ के साथ, श्री विजय अमृत कुलंगे (आईएएस), कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, गंजाम से मिले। एसआईओ ने एनआईसी द्वारा कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं और जिला शासन मोबाइल ऐप चैलेंज (डीजीएमसी) के तहत हाल ही में आयोजित मोबाइल ऐप चुनौती के बारे में भी जानकारी दी। SIO ने ऑटो एस्केलेशन प्रक्रिया के साथ LRMS सॉफ्टवेयर में नवीनतम संशोधन के बारे में सूचित किया। श्री सुभाष चंद्र मिश्रा, डीआईओ, और श्री एस.के. मोडल, एडीआईओ, एनआईसी, गंजाम ने जिला प्रशासन के लिए एनआईसी, गंजाम की कार्यधारा की हाल की गतिविधियों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। श्री कुलंगे ने गंजाम जिले के दौरे के लिए एसआईओ और एएसआईओ को धन्यवाद दिया और परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए

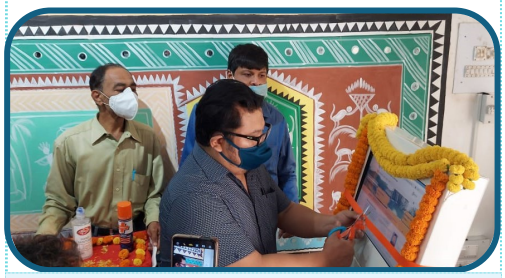

श्री टी. एओ, आईएएस, आरडीसी ने वेबसाइट का शुभारंभ किया

संयुक्त रूप से काम करने का आश्वासन दिया।

एसआईओ और एएसआईओ ने राजस्व मंडल आयुक्त (दक्षिणी मंडल), बरहमपुर में एनआईसी इकाई का भी दौरा किया और राजस्व मंडल आयुक्त (आरडीसी) श्री टी. एओ, आईएएस और आरडीसी की सचिव सुश्री सुजाता साहू, आईएएस से मुलाकात की। उन्होंने आरडीसी और उनके सचिव के साथ विस्तार से चर्चा की। आरडीसी ने S3waaS प्लेटफॉर्म के तहत आरडीसी (एसडी) कार्यालय, बरहमपुर के लिए एक वेब साइट विकसित करने में एनआईसी के काम की सराहना किए। आरडीसी ने एनआईसी टीम द्वारा विकसित वेब साइट https://rdcsdbmp.nic.in भी लॉन्च किए।

श्रीमती दास ने गजपति का भी दौरा किया, जहां एनआईसी, गजपति द्वारा विकसित एक एंड्रॉइड आधारित मोबाइल ऐप "सूचना प्रणाली गजपति जिला" को जिला कलेक्टर श्री अनुपम साहा, आईएएस और श्रीमती दास द्वारा लॉन्च किया गया। श्री टी. बालाक्रिश्ना मुर्ती, डी.आई.ओ., गजपति के अनुसार यह एप्प महत्वपूर्ण जिला कार्यालयों की नवीनतम जानकारी के साथ-साथ नागरिकों को संपर्क नंबर प्रदान करता है। श्री साहा ने श्रीमती दास को उनके दौरा के लिए धन्यवाद दिए और ऐप के विकास की सराहना किए ।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से अखिल भारतीय डिजिटल सेवा समाधान

एनआईसी संभावित विचारों की पहचान करने और एक स्थायी उत्पाद बनने तक उनका समर्थन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। एनआईसी ने कम समय में डिजिटल समाधानों की मांग और उनके कमीशनिंग में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है। इस प्रकार, यह कस्टम-निर्मित परियोजनाओं से सॉफ्टवेयर उत्पादों में स्थानांतरित हो गया। ईऑफिस, GePNIC, सुधार करने में मदद करता है, फाइलों के निर्माण, फाइल में नोट करने, निर्णय लेने जैसी कार्यक्षमता प्रदान करके निर्णय लेने में पारदर्शिता बढ़ाता है। विभिन्न स्तरों पर, और अंत में पत्रों और अधिसूचनाओं के रूप में निर्णय जारी करना। जबकि "GePNIC" (https://gepnic.gov.in) 72 लाख निविदाओं के साथ सरकारी विभाग और संगठन की खरीद और निविदा आवश्यकताओं को

एनआईसी का अखिल भारतीय डिजिटल सेवा समाधान

eCourts, eHospital, eCabinet, और कई अन्य लोगों से - NIC ने उत्पादीकरण के लिए एक मजबूत कौशल का प्रदर्शन किया है। एनआईसी का ई-अस्पताल (https://ehospital.gov.in) एप्लिकेशन वन-स्टॉप समाधान है जो मरीजों, अस्पतालों और डॉक्टरों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ने में मदद करता है। अब तक 493 अस्पताल इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। एनआईसी द्वारा विकसित ई-ऑफिस (https://eoffice.gov.in/) एप्लिकेशन सरकार को उत्पादकता और इसकी आंतरिक प्रक्रियाओं में पूरा कर रहा है। "ई-कोर्ट" और "ई-जेल" परियोजनाएं भी हमारे देश की न्यायपालिका प्रणाली को मजबूत करने में मदद कर रही हैं। कम समय में एक कस्टम वर्कफ़्लो आधारित सिस्टम विकसित करना हमेशा मुश्किल होता है, इसलिए, एक उच्च कॉन्फ़िगरेशन जेनेरिक सिस्टम "सर्विस प्लस" के विचार के साथ विकसित किया गया है। यह एक मेटा-डेटा आधारित ई-सेवा वितरण ढांचा है जो नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक-सेवाएं प्रदान करने के लिए Low-Code-NoCode (LCNC) वास्तुकला पर बनाया गया है। यह एक मंच पर 31 राज्यों से संबंधित 2000 से अधिक सेवाओं के साथ लॉन्च होने वाले सबसे सफल उत्पादों में से एक साबित हुआ है। एनआईसी या "एससीएपी-एनआईसी" का बीज प्रमाणन स्वचालन उत्पाद भी विकसित किया गया है जो ओडिशा और उत्तराखंड राज्य में तैनात बहु किरायेदारी प्रणाली को समाप्त करने के लिए एक प्रयास है। इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय रोलआउट के लिए भी चुना गया है। अंत में, "पी-बॉक्स" जो एक परीक्षा की ऑटो मॉनिटर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति का उपयोग करता है, एनआईसी का एक उत्पाद है। यह अत्यधिक नेटवर्क फ्लेक्सिबल मोड में काम कर सकता है जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को बहुत मदद मिल सकती है।

उम्मीद है कि इस तरह के और उत्पाद राष्ट्र के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आएंगे।